# लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास

मुफ्त बिजली

मोर्डन शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य

बाढ़, सुखाड़,
और बेरोजगार मुक्त बिहार

नया बिहार...
युवा बिहार

# धर्म न जात-करे सबकी बात

## लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास

221/A श्री कृष्णापुरी, चिल्ड्रेन पार्क के नजदीक, बोरिंग रोड, पटना -1

E-mail - biharlokjanshaktiparty@gmail.com

**जय हिन्द** **जय बिहार**

मेरा बिहार मेरा अभिमान रहा है, जिसकी पहचान सदियों से रही है। माता सीता, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध व गुरू गोबिन्द सिंह जैसी दिव्य शक्तियों का प्रवास बिहार की गौरवशाली धरती पर रहा है। "एक भारत" की रचना करने की कल्पना करने वाले महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिक गुरू आचार्य चाणक्य का जीवन मेरे बिहार से जुड़ा रहा है और उनके जीवनकाल में चन्द्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे विश्वव्यापी महान शासक बिहार की मिट्टी ने दिए। जहां एक ओर शिक्षा, साहित्य और वीरता के क्षेत्र में बिहार की धरती ने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, राष्ट्र कवि दिनकर, शेरशाह सूरी, बाबू वीर कुँवर सिंह जैसे रत्न दिये वहीं दूसरी तरफ देश की आजादी में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने में भी बिहारी पीछे नहीं रहे। महात्मा गांधी ने भी 1917 में चम्पारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरूआत बिहार से ही की। स्वतंत्र भारत को भी बिहार की ही मिट्टी ने पहला राष्ट्रपति देशभक्त राजेन्द्र बाबू के रूप में दिया और आजाद भारत में बिहार की संरचना स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण बाबू ने की। फिर वहीं जब देश के राजनीतिक हालात गिरने लगे तो बिहार की धरती पर पनपे जन आक्रोश ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जननायक कर्पूरी ठाकुर एवं अन्य ने देश की सत्ता को ही बदल दिया था। इसी संपूर्ण क्रांति, आंदोलन ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त सामाजिक न्याय का अध्याय दिया। जिसको चरितार्थ करने के लिए दलित सेना व लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक श्री राम विलास पासवान जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इन सब महान विभूतियों ने बिहार को संवारने का काम किया लेकिन उसके बावजूद बिहार अपनी अस्मिता खोता गया। आज बिहारी शब्द को एक गाली बना दिया गया है लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बिहारी हूँ और यह गर्व मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूँ। आज के मौजूदा हालात में हर बिहारी की ख्वाहिश है कि बिहारी अस्मिता के साथ–साथ बिहार को पुनः गौरवशाली बनाया जाए। इस सोच को यथार्थ करने के लिये लोक जनशक्ति पार्टी ने "बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट" के तहत लगभग चार लाख बिहारियों से सुझाव लेकर एक ऐसी रूप रेखा तैयार की जिससे बिहार को फर्स्ट बनाया जा सके।

आप सभी से यह अनुरोध है कि बिहार को फर्स्ट बनाने में अपना योगदान दें।

आपका बेटा

(चिराग पासवान)

# स्वास्थ्य

- अनुमण्डल स्तर पर किडनी डायलिसिस सेंटर, कैंसर जांच मशीन, डायबिटीज जांच की व्यवस्था व आंखों के जांच की व्यवस्था के साथ–साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता निश्चित की जाएगी।
- सरकारी अस्पतालों में शवों के लिए समर्पित मुफ्त परिवहन की व्यवस्था कराई जाएगी। (शव वाहन)
- सभी प्रखण्ड में चिकित्सा हेतु **24x7** एम्बुलेंस की संख्या बढ़ायी जाएगी।
- प्रत्येक जिले में एक डॉक्टर व कम्पाउंडर के साथ सभी संसाधनों से युक्त चलित अस्पताल **365** दिन उपलब्ध रहेगा।
- सभी सरकारी अस्पतालों में जरूरतमन्दों को मुफ्त दवा की व्यवस्था एवं वितरण में हो रही घपलेबाजी को दूर करने के लिये स्वास्थ्य विभाग शिकायत निवारण हेतु टॉल फ्री नम्बर जारी करेगा ताकि सरकार यह सुनिश्चित कर पाये कि सभी दवा मौजूद है और निःशुल्क वितरण हो रहा है।
- जेनेरिक दवाईयों की भी उपलब्धता सरकार कराएगी।

- प्रदेश में अत्याधुनिक स्तर के दो कैंसर संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- बच्चे के जन्म के एक साल के अंदर मुफ्त में मेडिकल टेस्ट कराकर अनिवार्य रूप से हेल्थ कार्ड दिया जाएगा एवं केन्द्र सरकार की मदद के अतिरिक्त ढ़ाई लाख रूपये तक की मदद प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी।
- सभी जिला अस्पतालों में पैथोलॉजी विभाग को बेहतर किया जाएगा।
- सभी निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुविधा के लिए दी जाने वाली 10 प्रतिशत निःशुल्क सुविधा को सख्ती से लागू किया जाएगा।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लाकर **CGHS** की तर्ज पर **SGHS** जैसा प्रावधान कर उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को चुनिंदा सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों में बहाल किया जाएगा।
- वेटनरी कम्पाउंडर, ड्रेसर (पशु व जानवर के लिए) की पढ़ाई की शुरूआत की जाएगी।

**बिहार 1st**
**बिहारी 1st**

# शिक्षा

- **(UPSC/IIT/IIM)** और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा, मुखर्जी नगर व प्रयागराज की तर्ज पर कोचिंग सिटी प्रदेश में बनाया जाएगा जिसमें छात्रावास एवं पुस्तकालय की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की जाएगी।
- प्रदेश के हर अनुमंडल में वाणिज्य, कला, कानून और अन्य पाठ्यक्रमों के साथ–साथ छात्रावास युक्त नये कॉलेज खोले जाएंगे।
- स्थानीय भाषा को स्कूली शिक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में जोड़ा जाएगा।
- जरूरतमंदों व योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिये सरकार बिना ब्याज के लोन देगी।
- बिहार में प्रत्येक दो जिलों पर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा व सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में भवन, शौचालय और पठन–पाठन संबंधित सुविधा बढ़ाई जाएगी।
- शिक्षकों के वेतनमान में अंतर को दूर कर सही समय पर वेतन की व्यवस्था की जाएगी।
- राज्य के पाठ्‌यक्रम में संविधान और आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. की पढ़ाई को जोड़ा जाएगा।
- राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रक की बहाली आयोग के माध्यम से होगी।
- राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा कैलेण्डर बनाकर सत्र को नियमित किया

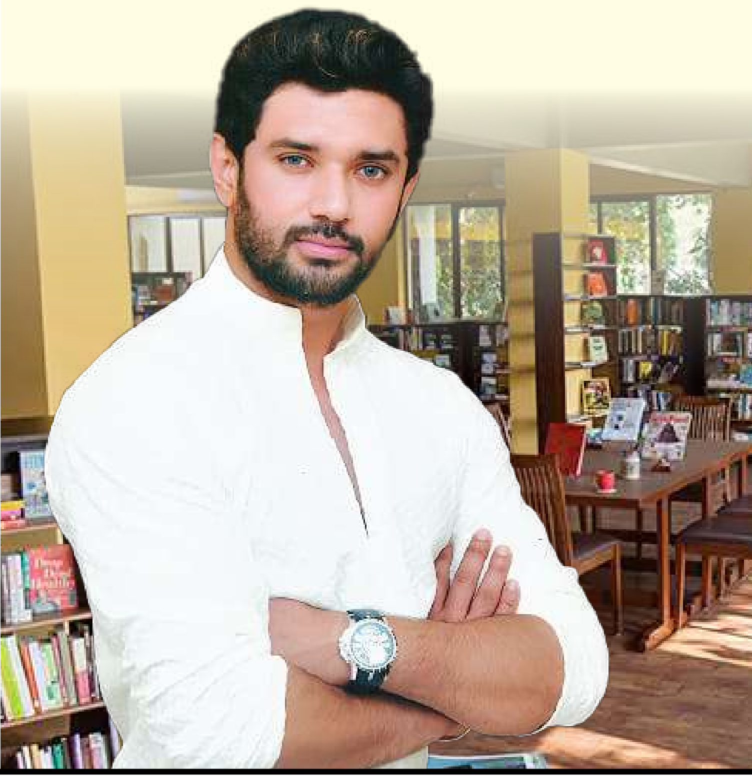

जायेगा ताकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को क्रमशः 3 वर्ष और 2 वर्ष में पूर्ण करवाने को सुनिश्चित किया जा सके। अभी यह बीते कई वर्षों से क्रमशः 5 वर्ष में ग्रेजुएशन और 3 से 4 वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। छपरा स्थित जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय इसका बड़ा उदाहरण है।

- राज्य के सभी जिलों में बी.एड् की पढ़ाई हो इसे सरकार सुनिश्चित करेगी।
- राज्य के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में खाली पड़े लाईब्रेरियन एवं लैब टेक्नीशियन के पदों पर बहाली अविलंब की जाएगी।
- अनुसूचित जाति–जनजाति छात्रावास को वाई–फाई, लाईब्रेरी, मेस, खेलकूद सामग्री व सुरक्षा गार्ड के साथ आधुनिक स्तर का बनाया जाएगा।
- राज्य के सभी विद्यालय, महाविद्यालय में फिजिकल टीचर की बहाली की जाएगी।
- हर प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं के लिये कुछ सीटें रिजर्व होगी।

- राज्य के सभी हाई स्कूल को 12वीं तक की मान्यता दी जायेगी व उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को 12वीं के स्तर पर विकसित किया जाएगा।
- सिमुलतला आवासीय विद्यालय के तर्ज पर प्रत्येक जिला में आवासीय विद्यालय बनाये जाएंगे।
- राज्य के दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लुई ब्रेल के नाम पर देहरादून स्थित संस्थान के तर्ज पर एक विद्यालय सह शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा।
- प्रदेश में प्राइवेट संस्थानों को प्रोफेशनल पढ़ाई करवाने हेतु सरकार पी.पी.पी. मॉडल के तहत जमीन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

# उद्योग

- आई.टी. पार्क की स्थापना के साथ इकोनॉमिकल जोन को राज्य में बढ़ाया जायेगा एवं अन्य सुविधाओं से जोड़ा जाएगा जिससे आई.टी. कम्पनी व अन्य कम्पनियां बिहार में आ सकें।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सिंगल विन्डों सिस्टम व तय समय सीमा नियम को लागू किया जाएगा और तय समय सीमा पर फाइल पास न होने पर अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को लगाने के नाम पर ली गईं किसानों की जमीनों को चिन्हित कर लीज़ को रद्द करते हुए नए व्यक्ति को आवंटित किया जाएगा जो तय समय सीमा में वहाँ उद्योग लगा सके।
- अंतरराज्यीय अथवा विदेशों में काम के लिए जाने वाले बिहारी कामगारों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा ताकि सुरक्षा के साथ बिहारी पुरी दुनिया में काम कर सके।
- मछली उत्पादन को राज्य सरकार के संरक्षण में रोजगार के बड़े मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- व्यवसाय करने के लिये बिना शर्त बैंकों से लोन दिया जाएगा।

- राज्य के सभी छोटे बाजार में सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पु चलाने वाले, मछली बेचने वाले इत्यादि खासकर छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों को चिन्हित करके सरकारी स्तर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि उन्हें सूद लेने वालों से बचाया जा सके।
- ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट उत्तीर्ण या पास किए हुए बेरोजगारों को व्यवसाय के लिए आसानी से ब्याज मुक्त लोन मिलेगा।
- जिलेवार अथवा कमिश्नरी स्तर पर ''बिहार मेला'' लगाकर जिला हस्तकौशल योजना के तहत स्थानीय हस्तकलाओं को प्रोत्साहित कर उनके लिए निर्यात हेतु बाजार तैयार किया जाएगा।
- राज्य के सभी बाजारों में सार्वजनिक शौचालय पी.पी.पी. मॉडल के तहत बनाये जाएंगे एवं उनके रख–रखाव की भी व्यवस्था की जाएगी।
- लिट्टी चोखा स्टॉल बिहार के हर पर्यटन स्थल व बाजार में सरकारी मदद से खोले जाएंगे।

# रोजगार/पलायन

- सरकार के सभी विभागों में अनुमोदित व स्वीकृत खाली पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाएगा।
- नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा।
- नियोजित कर्मचारियों को भी समान काम समान वेतन दिया जाएगा।
- इस बात की पूरी व्यवस्था की जाएगी कि सरकारी और निजी क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर छंटनी के शिकार न बनें एवं मिनिमम वेतन एक्ट के तहत उनको मजदूरी प्राप्त हो। इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।
- प्रदेश सरकार रोजगार पोर्टल बनाएगी जहां रोजगार लेने वाला और देने वाला सीधा जुड़ सकेगा।
- राज्य सरकार में जो भी कर्मचारी संविदा पर कार्यरत है उनको नियमित किया जाएगा।
- बिहार के सभी विद्यालयों में गार्ड की बहाली की जाएगी।
- होम गार्ड की नौकरी नियमित की जाएगी।
- 10 वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और उनका वेतन दूसरे प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के समान किया जाएगा।
- योग शिक्षकों की बहाली होगी।
- बिहार के बाहर रह रहे बिहार वासियों की सुरक्षा के लिए हेल्प लाइन नम्बर जारी किया जाएगा एवं कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में विभाग गठित किया जाएगा ताकि किसी भी बिहार वासी के साथ अन्य प्रदेशों में कोई अप्रिय घटना न घट सके और घटित होने पर त्वरित कार्रवाई हो।

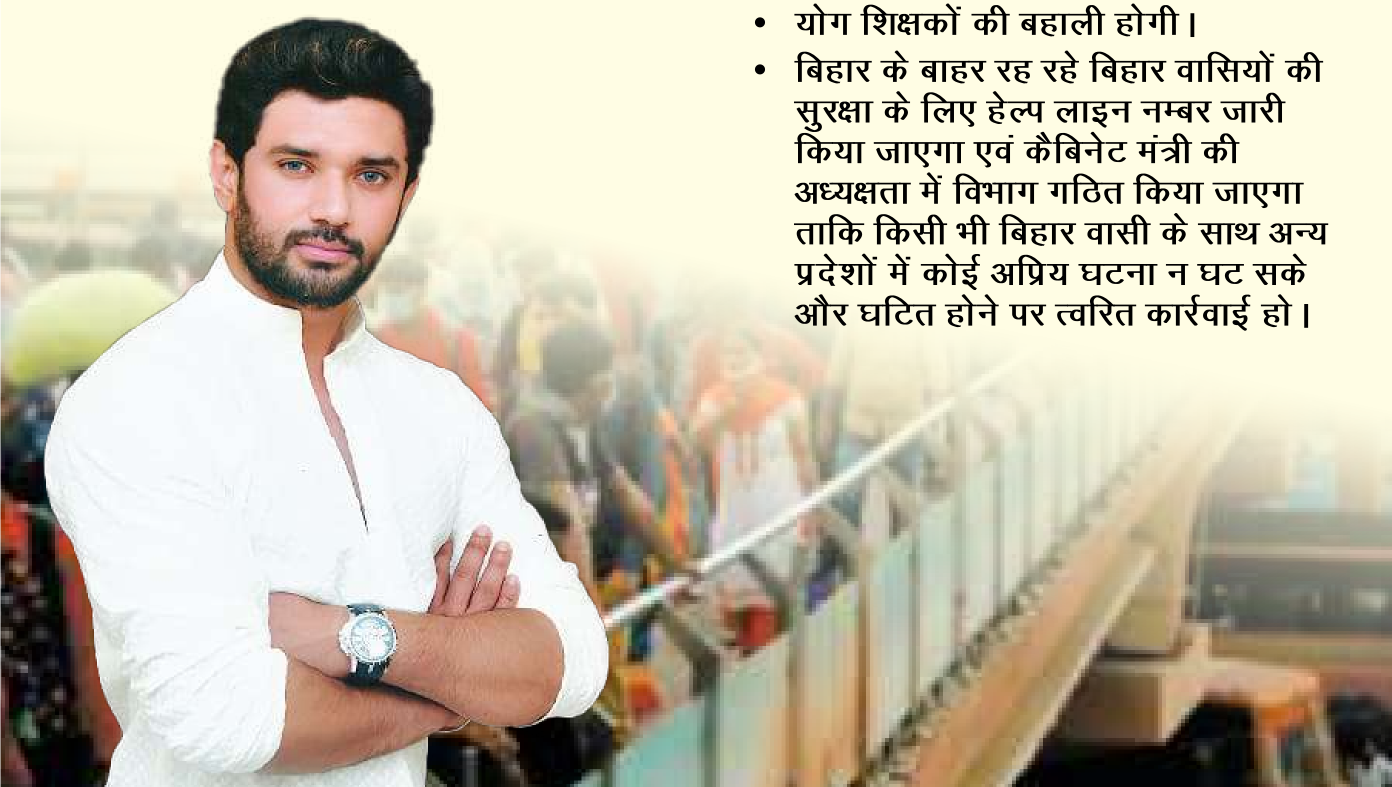

# नारी शक्ति व सशक्ति करण

- कम्यूनिटी मोबलाइसर जीविका मित्र को वेतन दिया जाएगा।
- आशा समूहों में जो कार्यरत हैं उन्हें कमीशन की जगह वेतन दिया जाएगा।
- आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रति माह रु. 7500 वेतन दिया जाएगा।
- महिला पुलिस कर्मियों के लिए प्रदेश के सभी थाना या हेडक्वार्टर में अलग से आवास एवं शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।
- महिलाओं की स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रभावी कार्यक्रम चलाये जाएंगे।
- सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है एवं इसके लिए विधान सभा से प्रस्ताव पास कर पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को बाध्य करेगी।
- गर्भावस्था–माँ अन्न योजना (नई योजना) के तहत छठवें महीने से प्रसव तक पौष्टिक भोजन व 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा।
- सामुहिक विवाह का आयोजन बड़े पैमाने पर हर प्रखण्ड में सरकार द्वारा किया जाएगा।
- असहाय एवं जरूरतमंद महिलाओं को आवास एवं पेंशन की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
- जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा।
- महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- सभी प्रखण्ड मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं बाजार में महिलाओं के लिये अलग से शौचालय बनाया जाएगा।
- गर्भवती महिलाओं के लिये प्रत्येक पंचायत में जांच की सुविधा एवं प्रत्येक माह में डॉक्टर की उचित सलाह की व्यवस्था की जाएगी।
- आंगनबाडी केन्द्र को सुविधा युक्त किया जाएगा।
- प्रत्येक अनुमंडल में महिला महाविद्यालय छात्रावास के साथ स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता होगी।
- राज्य के सभी स्कूलों व कॉलेजों में बिहार की बेटियों के लिए अलग से शौचालय बनवाया जाएगा ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो और सम्मानपूर्वक वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें।

# कृषि/गन्ना/मत्स्य/ डेयरी/सहकारिता

- खेती कौशल मिशन – आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बिहार की कृषि व्यवस्था विश्व स्तरीय हो पाये।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा किसानों का भुगतान निश्चित समय पर हो अन्यथा अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होगी।
- पैक्सों को अनुदान के रूप में कृषि यन्त्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- बैद्यनाथन समिति की अनुशंसा के आलोक में पूर्ववित्त योजनान्तर्गत पैक्सों और सहकारी बैंको को 2008 से ही केन्द्र सरकार से बकाया राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पैक्स और सहकारी बैंक की स्थिति सुदृढ़ हो सके।
- राज्य खाद्य निगम द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने के कारण पैक्सों पर लगने वाले अतिरिक्त सूद को माफ किया जाएगा तथा पूर्व बकाया अतिरिक्त सूद की राशि 360 करोड़ का बजट में प्रावधान करके माफ किया जाएगा।
- पैक्स अध्यक्षों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा।
- सभी पंचायतों में पैक्स के माध्यम से गोदाम उपलब्ध हो, यह सरकार सुनिश्चित करेगी।

- बिहार में दूध उद्योग को प्राथमिकता देकर चरणबद्ध तरीके से डेनिश मॉडल (डेनमार्क मॉडल) बनाया जाएगा।
- बन्द चीनी मिलों को चालू कर उनमें उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा व किसानों को भुगतान सही समय पर हो यह आयोग की निगरानी में सुनिश्चित किया जाएगा एवं बिहार के पड़ोसी राज्यों की तुलना में गन्ने का मूल्य तय किया जाएगा।
- सभी व्यवसायिक खेती के लिए सरकार आर्थिक सहयोग करेगी।
- मखाना की खेती में सरकार सहयोग देगी व लोकल मार्केट बनाएगी।
- मक्का की खेती में सरकार सहयोग देगी व लोकल मार्केट बनाएगी।

- स्थानीय पैदावार को बढ़ावा देने के लिये सरकार सहयोग देगी व लोकल मार्केट बनाएगी।
- फूड प्रोसेसिंग यूनिट को प्राथमिकता के आधार पर सभी जरूरतमंद जिलो में स्थानीय उपज के आधार पर लगाया जाएगा।

बिहार 1st
बिहारी 1st

# बाढ़/सूखा

- बाढ़ और सूखे को रोकने के लिए राज्य की सभी नदियों को कैनाल बनाकर जोड़ा जायेगा।
- टाल (विरान) क्षेत्र को कैनाल के माध्यम से कृषि के लिए जोड़ा जाएगा।
- राज्य में जो बरसात का पानी पहाड़ के तट से वर्षा होने पर बह जाता है उसे बांध बनाकर सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा।
- कोसी नदी पर हाईडल पावर स्टेशन (जल विद्युत परियोजना) स्थापित किया जाएगा ताकि सम्पूर्ण बिहार को बिजली मिल सके।
- नहरों का पुनरुद्धार कर उनमें पानी के प्रवाह को सुनिश्चित किया जाएगा और उनके अतिक्रमण को समाप्त किया जाएगा।

# आवासीय/बिल्डिंग/शहरी एवं ग्रामीण विकास

- सभी पर्चा धारियों को जिन्हें कब्जा नहीं मिला है उन्हें कब्जा दिलवाया जाएगा व जिन्हें पर्चा नहीं मिला है उन्हें पर्चा दिलाया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखण्ड में सुविधा युक्त विवाह भवन/बारात घर बनाया जाएगा।
- नया सर्वेक्षण करवाकर छूटे हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नई योजना(बंगला योजना) के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- आवासीय योजना के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों व पूर्व अधिकारियों को सस्ते दरों पर जिलों में आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- सभी अवकाश प्राप्त सैन्य कर्मियों को सस्ते दर पर आवास दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।
- किन्नरों को बंगला योजना से जोड़ा जाएगा।
- जनजातियों को बंगला योजना से जोड़ा जाएगा व पक्का घर बनाकर दिया जाएगा।
- पटना को विश्व स्तरीय शहर बनाया जाएगा व साथ में हर प्रमंडल के किसी एक शहर का शहरीकरण आधुनिक स्तर पर किया जाएगा।
- हर प्रखण्ड में योग आश्रम और टहलने हेतु उद्यान की व्यवस्था की जाएगी।

बिहार 1st
बिहारी 1st

# मीडिया व वकील

- वकील भाईयों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- वकील भाईयों को एक्सिडेंटल पॉलिसी दी जाएगी।
- बजट में विशेष प्रावधान कर सभी जिला न्यायालयों को आधुनिक व सुविधामय किया जाएगा।
- मीडिया के साथियों को सस्ते दर पर आवास दिया जाएगा।
- सभी जिलों में मेस एवं वाईफाई युक्त आधुनिक प्रेस क्लब बनाया जाएगा।

# कानून/सुरक्षा

- आम जनता के लिए पुलिस हेल्प लाइन 100 नम्बर की सुविधा पूरे प्रदेश में सुदृढ़ की जाएगी ताकि 10 मिनट में पुलिस आपकी सहायता हेतु पहुंच सके।
- महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा से बचाव के लिए सरकार युवतियों को प्रशिक्षित करेगी।
- प्रत्येक 6 माह में पुलिस अधिकारियों का फिटनेस टेस्ट होगा।
- प्रत्येक प्रखण्ड में महिला थाना की स्थापना की जाएगी।
- महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए सभी जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा।
- राज्य के प्रत्येक कारागार में हर महीने निर्दोष फंसाये गये विचाराधीन बंदियो की रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सरकार के स्तर से रिहा कराया जाएगा ताकि लोगों में कानून के प्रति विश्वास पैदा हो।
- भू–माफिया नियंत्रण – एक्शन प्लान बनाकर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी।
- बालु माफिया नियंत्रण – एक्शन प्लान बनाकर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी।
- माइनिंग कानून बनाकर पहाड़ों की हिफाजत की जाएगी ताकि अवैध खनन ना हो सके।
- पुलिस विभाग में कार्य कर रहे कर्मियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन की छुट्टी सुनिश्चित की जाएगी।
- ऑनलाईन एफ.आई.आर. की व्यवस्था बिहार में लागू की जाएगी।
- पुलिस कर्मियों को कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा।

# शासन

- बिहार में पनप रहे अफसरशाही को जड़ से समाप्त किया जाएगा।
- सात निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जायेगा व लम्बित राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा ताकि कार्य पूरा हो सके।
- टोल फ्री हेल्प लाईन नम्बर के साथ सरकार ऐप लॉच करेगी जिसके माध्यम से किसी भी सरकारी विभाग की शिकायत दर्ज हो सकेगी और तय समय–सीमा में उस शिकायत का निष्पादन किया जाएगा।
- नये जिले, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड बनाये जायेंगे ताकि प्रदेश वासियों की समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके।
- हर प्रखण्ड मुख्यालय में सभी तरह के पहचान–पत्र के लिए सेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- हर प्रखण्ड मुख्यालय पर आम जनता के लिये अधिकारियों द्वारा उनके शिकायत के निवारण के लिए हर माह लोक चौपाल कार्यक्रम लगाया जाएगा।
- केन्द्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए सरकार एक ठोस ढांचा तैयार करेगी, जो इस बात की निगरानी करेगा कि इन योजनाओं का पूरा लाभ आम जनता और उस तबके तक पहुंच सके जिनके लिए

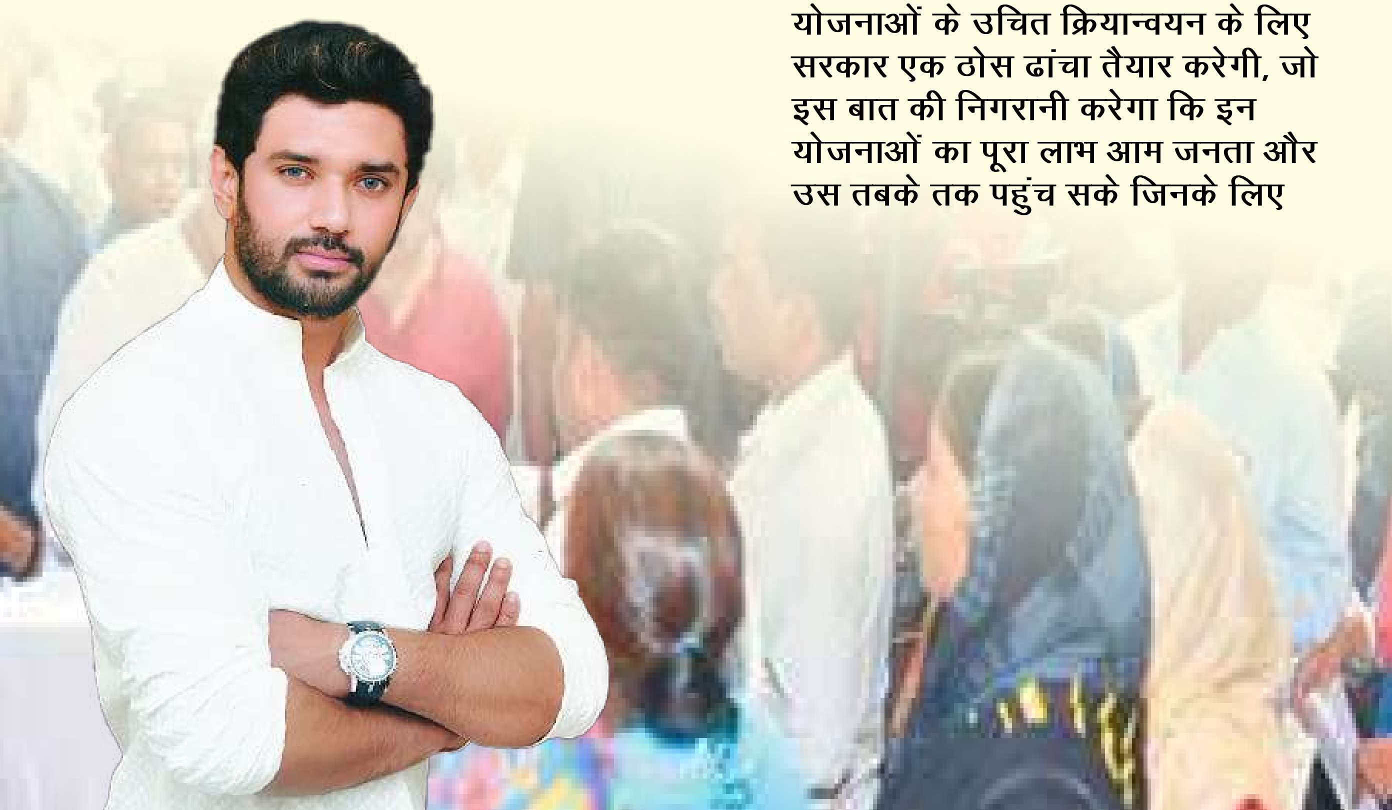

उक्त योजनाएं बनाई गई हैं। इसके लिए शीर्ष स्तर पर आईएएस स्तर का वरिष्ठ अधिकारी होगा जो सीधे कैबिनेट के प्रति जवाबदेह होगा।

- अनुसूचित जाति जनजाति को राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा।
- रसोईया का मासिक वेतन बढ़ाया जाएगा।
- असंगठित मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी दिलवाई जायेगी व पालन न होने पर कार्रवाई होगी।
- वृद्धा पेंशन योजना को बढ़ाया जाएगा।
- सीता रसोई योजना के तहत हर प्रखण्ड मुख्यालय पर 10 रु. में भोजन देने की व्यवस्था सरकार करेगी।
- समाज में ऐसे लोग जो किन्ही कारणों से अकेले रह रहे हैं उन्हें सहारा योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि समाज में वे भी अपनी भागीदारी निभा सकें।

- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं को दो रुपए प्रति किलो की दर से अतिरिक्त राशन मुहैया कराया जाएगा।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के यहां कन्या के जन्म का रजिस्ट्रेशन कराने पर 25 हजार रुपए के साथ ही कन्या के नाम पर बैंक खाता खोला जाएगा। 18 साल तक उसके नाम से जमा पैसे को उसके परिवार के लोग बैंक से न निकाल सकें, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- जनता को घर तक जनवितरण का अनाज उपलब्ध कराया जायेगा।
- दिव्यांगजनों का मासिक पेंशन बढ़ाया जायेगा।
- सरकार सभी प्रखण्ड में विधुत शवदाह गृह के साथ शमशान घाट में लाईट, शेड, प्लेटफार्म, शौचालय व पानी की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएगी।

- सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी प्राथमिकता के आधार पर करायी जाएगी साथ ही लाईट, शेड व पानी की व्यवस्था की जाएगी।
- वक्फ की संपत्तियों का समय–सीमा के तहत सर्वेक्षण करवाया जाएगा तथा राज्यस्तरीय कम्प्यूटरीकृत आंकड़े तैयार करवाए जाएंगे। इस तरह के सर्वेक्षण के आधार पर सम्पतियों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया जाएगा।
- सभी वक्फ सम्पत्तियों को विकसित किया जाएगा।
- मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- अल्पसंख्यक छात्रों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया जाएगा।
- वेटरनरी एम्बुलेंस सभी विधान सभा में दी जाएगी।
- समाज में विशेष योगदान देने वालों व शहीदों के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा।
- पूर्व सैन्य कर्मियों को हथियारों का लाइसेंस मिलना आसान होगा ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हे नौकरी मिलने में आसानी हो।

# साहित्य/संस्कृति/युवा/खेल

- बिहार में फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी व फिल्म सम्बंधी टेक्निकल पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी।
- एनएसडी के तर्ज पर नाट्य विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए युवा आयोग का गठन किया जाएगा।
- सभी जिलों मे मल्टीपल स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना की जाएगी व सभी प्रखण्ड में आधुनिक इन्डोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
- पटना में विश्वस्तरीय स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा सके ताकि बिहार के युवा खेल में देश का नाम रौशन कर सके।
- कक्षा 1 से पी.जी. तक के युवक और युवतियों के लिए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश में की जाएगी।

बिहार 1st
बिहारी 1st

## पर्यटन/परिवहन

- धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होगी।
- जैन तीर्थ स्थल को राज्य में सभी सुविधाओं के साथ तय समय सीमा में विकसित किया जाएगा।
- बौद्ध तीर्थ स्थलों को अत्याधुनिक सुविधा से लैस कर विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।
- गुरु गोबिन्द सिंह तीर्थ स्थल को सभी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तय समय सीमा में विकसित किया जाएगा।
- भगवान महावीर जैन सर्किट को 6 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा।
- भगवान बुद्ध सर्किट को 6 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा।
- सीतामढ़ी से अयोध्या जाने वाली सड़क को 6 लेन का बनाया जाएगा। (बिहार प्रदेश सीमा के अंदर तक)
- सरकार सूफी सर्किट बनाएगी।
- डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी के जन्मदिन 3 दिसम्बर को राष्ट्रीय मेधा दिवस के रूप में घोषित कर इस प्रस्ताव को विधान सभा में पारित कर केन्द्र सरकार को मानने पर बाध्य किया जाएगा।
- बिहार के सभी जिलों की समीक्षा कर ऐतिहासिक इमारतों को हेरीटेज संपदा घोषित किया जायेगा और पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।

- वीरशिरोमणी बाबा चौहरमल मंदिर मोकामा को धार्मिक पर्यटन के रूप में घोषित किया जाएगा। मंदिर तक पहुँचने के रास्ते के साथ आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा।
- बिहार स्टेट टूरिस्ट डेवपलेमेंट कारपोरेशन **(BSTDC)** व मंत्रालय के कामों में हो रहे व्यवधानों को दूर किया जाएगा।
- वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को जिम कॉर्बेट पार्क के तर्ज पर स्थापित किया जाएगा।
- रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद व अन्य पहाड़ी स्थानों को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा व एडवेंचर टूरिज्म से जोड़ा जाएगा।
- पर्यटन स्थलों की समीक्षा कर नये स्थानों को हर वर्ष जोड़ा जाएगा।
- पर्यटन स्थल के बढ़ावे में सरकार कई स्थानों पर पी.पी.पी. मॉडल अपनाएगी।
- चम्पारण सत्याग्रह यात्रा को गांधी सर्किट के रूप में पर्यटन स्थल बनाया जाएगा।
- सोनपुर पशु मेला की सुविधाओं को पुष्कर मेला में मिल रही सुविधाओं के तर्ज पर दिया जाएगा।
- वाटरस्पोर्ट्स (जल क्रीड़ा) को बढ़ावा दिया जाएगा।
- वैशाली स्थित प्रथम लिच्छवि गणराज्य स्थल को धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ''बराबर हिल केव्स'' को अजंता एलोरा की तर्ज पर टूरिज्म का केन्द्र बनाया जाएगा।
- बस सेवाओं और बस की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार किया जाएगा।
- सभी बस अड्डों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
- सभी आधुनिक सुविधायुक्त नई बसों के साथ इंटर–सिटी, इन्टर–स्टेट बस नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
- सरकार निजी कम्पनियों को बस के लिये परमिट प्रक्रिया आसान बनाएगी।
- सभी राज्य मार्गों पर जन सुविधा हेतु शौचालय व आपातकाल की सुविधा के साथ राज्य मार्ग में सुरक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी।
- ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जाएगा व रजिस्ट्रेशन राशि को कम किया जाएगा।

**बिहार 1st**
**बिहारी 1st**

मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ
जहाँ सदियों से अंधेरा है।

**वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए**
**और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज़ करने के लिए**

# मुख्य बिंदु

- बिहार में पनप रहे अफसरशाही को जड़ से समाप्त करेगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट।
- बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लागू होने से फूड प्रोसेसिंग यूनिट को प्राथमिकता के आधार पर सभी जिलों में लगाया जाएगा।
- बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लागू होने से सभी महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा मिलेगी।
- बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट समान काम समान वेतन लागू करेगा।
- बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सरकार के सभी विभागों के अनुमोदित व स्वीकृत पदों को शीघ्र भरेगा।
- बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लागू होने से प्रदेश में अत्याधुनिक स्तर के कैंसर संस्थानों की स्थापना हो पायेगी ।
- बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट युवा आयोग का गठन कराएगा।
- बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लागू होने से राज्य में कोचिंग सिटी की स्थापना होगी।
- माता सीता का भव्य मंदिर निर्माण कर दुनिया के मानचित्र पर लाएगा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट।
- सभी निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुविधा के लिए दी जाने वाली 10 प्रतिशत निःशुल्क सुविधा को सख्ती से लागू किया जाएगा।
- राज्य सरकार के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लाकर CGHS की तर्ज पर SGHS जैसा प्रावधान कर उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को चुनिंदा सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों में बहाल किया जाएगा।
- (UPSC/IIT/IIM) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा, मुखर्जी नगर व प्रयागराज की तर्ज पर कोचिंग सिटी प्रदेश में बनाया जाएगा जिसमें छात्रावास एवं पुस्तकालय की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की जाएगी।
- अनुसूचित जाति–जनजाति छात्रावास को वाई–फाई, लाईब्रेरी, मेस, खेलकूद सामग्री व सुरक्षा गार्ड के साथ आधुनिक स्तर का बनाया जाएगा।
- हर प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं के लिये कुछ सीटें रिजर्व होगी।
- आई.टी. पार्क की स्थापना के साथ इकोनॉमिकल जोन को राज्य में बढ़ाया जायेगा एवं अन्य सुविधाओं से जोड़ा जाएगा जिससे आई.टी. कम्पनी व अन्य कम्पनियां बिहार में आ सकें।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सिंगल विन्डों सिस्टम व तय समय सीमा नियम को लागू किया जाएगा और तय समय सीमा पर फाइल पास न होने पर अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. किया जाएगा।
- प्रदेश सरकार रोजगार पोर्टल बनाएगी जहां रोजगार लेने वाला और देने वाला सीधा जुड़ सकेगा।
- राज्य सरकार में जो भी कर्मचारी संविदा पर कार्यरत हैं उनको नियमित किया जाएगा।
- बिहार के बाहर रह रहे बिहार वासियों की सुरक्षा के लिए हेल्प लाइन नम्बर जारी किया जाएगा एवं कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में विभाग गठित किया जाएगा ताकि किसी भी बिहार वासी के साथ अन्य प्रदेशों में कोई अप्रिय घटना न घट सके और घटित होने पर त्वरित कार्रवाई हो।
- कम्यूनिटी मोबलाइसर जीविका मित्र को वेतन दिया जाएगा।
- आशा समूहों में जो कार्यरत हैं उन्हें कमीशन की जगह वेतन दिया जाएगा।

- सभी प्रखण्ड मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं बाजार में महिलाओं के लिये अलग से शौचालय बनाया जाएगा।
- बिहार में दूध उद्योग को प्राथमिकता देकर चरणबद्ध तरीके से डेनिश मॉडल (डेनमार्क मॉडल) बनाया जाएगा।
- फूड प्रोसेसिंग यूनिट को प्राथमिकता के आधार पर सभी जरूरतमंद जिलो में स्थानीय उपज के आधार पर लगाया जाएगा।
- बाढ़ और सूखे को रोकने के लिए राज्य की सभी नदियों को कैनाल बनाकर जोड़ा जायेगा।
- नया सर्वेक्षण करवाकर छूटे हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नई योजना (बंगला योजना) के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- किन्नरों को बंगला योजना से जोड़ा जाएगा।
- वकील भाईयों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- वकील भाईयों को एक्सिडेंटल पॉलिसी दी जाएगी।
- मीडिया के साथियों को सस्ते दर पर आवास दिया जाएगा।
- आम जनता के लिए पुलिस हेल्प लाइन 100 नम्बर की सुविधा पूरे प्रदेश में सुदृढ़ की जाएगी ताकि 10 मिनट में पुलिस आपकी सहायता हेतु पहुंच सके।
- ऑनलाईन एफ.आई.आर. की व्यवस्था बिहार में लागू की जाएगी।
- पुलिस कर्मियों को कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा।
- बिहार में पनप रहे अफसरशाही को जड़ से समाप्त किया जाएगा।
- सात निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जायेगा व लम्बित राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा ताकि कार्य पूरा हो सके।

- सीता रसोई योजना के तहत हर प्रखण्ड मुख्यालय पर 10 रु. में भोजन देने की व्यवस्था सरकार करेगी।
- सरकार सभी प्रखण्ड में विधुत शवदाह गृह के साथ शमशान घाट में लाईट, शेड, प्लेटफार्म, शौचालय व पानी की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएगी।
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता होगी।
- जैन तीर्थ स्थल को राज्य में सभी सुविधाओं के साथ तय समय सीमा में विकसित किया जाएगा।
- बौद्ध तीर्थ स्थलों को अत्याधुनिक सुविधा से लैस कर विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके।
- वीरशिरोमणी बाबा चौहरमल मंदिर मोकामा को धार्मिक पर्यटन के रूप में घोषित किया जाएगा। मंदिर तक पहुँचने के रास्ते के साथ आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा।
- वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को जिम कॉर्बेट पार्क के तर्ज पर स्थापित किया जाएगा।
- पर्यटन स्थल के बढ़ावे में सरकार कई स्थानों पर पी.पी.पी. मॉडल अपनाएगी।
- बिहार में फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी व फिल्म सम्बंधी टेक्निकल पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी।
- पटना में विश्वस्तरीय स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की जा सके ताकि बिहार के युवा खेल में देश का नाम रौशन कर सके।

पिछले 50 साल से निरंतर देश व बिहार वासियों की सेवा में मैंने अपने जीवन को समर्पित किया। हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि कैसे भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। सक्रिय राजनीतिक जीवन में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे पर कड़ी मेहनत के कारण कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बना। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे छह–छह प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। केन्द्र सरकार के माध्यम से बिहार के विकास के लिए जितना मुझसे बन पाया मैंने प्रयास किया। केन्द्र सरकार का हिस्सा होने के बावजूद मुझे इस बात का अहसास हुआ कि जब तक राज्य में अपनी सरकार न हो तो केन्द्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना संभव नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ सन् 2000 में मैंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। पिछले 20 साल में पार्टी अच्छे–बुरे दौर से उभरते हुए यहां तक आई है। अब चिराग के मजबूत कंधों के साथ व बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है।

कोरोना संकट के समय खाद्य मंत्री के रूप में निरंतर अपनी सेवा देश को दी और हरसंभव प्रयास किया कि सभी जगह खाद्य सामग्री समय पर पहुंच सके। इसी दौरान तबियत खराब होने लगी लेकिन काम में कोई ढ़िलाई न हो इसलिए अस्पताल नहीं गया। मेरी खराब तबियत का एहसास जब चिराग को हुआ तो उसके कहने पर मैं अस्पताल में अपना इलाज कराने आ गया।

आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो चिराग के कंधों पर बढ़ती हुई जिम्मेदारियों का अहसास कर पा रहा हूँ। जहाँ वो एक तरफ इस बीमारी से लड़ने में दिन–रात मेरी मदद कर रहा है वहीं दूसरी तरफ बिहार की अस्मिता की लड़ाई भी लड़ रहा है। 50 सालों में आज पहली बार बिहार में एक ऐसा चुनाव आया है जिसमें मैं स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय रूप से अपनों के बीच रहने में असमर्थ हूँ जिसका मुझे दुःख है। पहली बार मेरा बेटा चिराग मेरे बिना इस विधान सभा चुनाव में अकेला होगा। मुझे अपने बेटे चिराग पर गर्व है कि चिराग ने मेहनत कर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट बिहार को और बिहारियों को पहले स्थान पर ले जाने के लिए बनाया है। मेरा विश्वास है कि समस्त बिहार के लोग चिराग द्वारा चलाई गई मुहिम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन का समर्थन करेंगे ताकि बिहार को फर्स्ट बनाया जा सके।

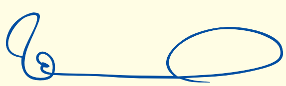

(राम विलास पासवान)